भारत सरकार

इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1487

जिसका उत्तर 28 जुलाई, 2021 को दिया जाना है।

6 श्रावण, 1943 (शक)

डिजिटल इंडिया कार्यक्रम

1487. श्री ओम पवन राजेनिंबालकर :

श्री संजय जाधव :

क्या इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पूरे देश में डिजिटल इंडिया कार्यक्रम की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ख) क्या सरकार के पास सूचना और सेवा केन्द्रों के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्र के गांवों में संचार बढ़ाने के लिए कोई योजना या परियोजना है;

(ग) यदि हां, तो विशेषकर महाराष्ट्र के संबंध में तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार ने ऐसे क्षेत्रों में कार्यरत गैर-सरकारी संगठनों को उक्त सेवा केन्द्र प्रदान करने का कोई निर्णय लिया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ड.) उक्त कार्यक्रम ने ग्रामीण क्षेत्रों को किस प्रकार प्रभावित किया है ?

उत्तर

इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री (श्री राजीव चंद्रशेखर)

(क) : **अनुबंध-I** के अनुसार।

(ख) : इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के स्तंभ-3 के तहत सामान्य सेवा केंद्र (सीएससी) कार्यक्रम को कार्यान्वित कर रहा है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य नागरिकों को विभिन्न सरकार-से-नागरिकों (जी2सी) और अन्य नागरिक-केंद्रित ई-सेवाओं के वितरण के लिए देश भर में 2.50 लाख ग्राम पंचायतों (जीपी) में कम से कम एक सीएससी स्थापित करना है। यह एक आत्मनिर्भर उद्यमिता मॉडल है जो ग्राम स्तरीय उद्यमियों (वीएलई) द्वारा चलाया जाता है। जून, 2021 तक, देश भर में कुल 3,99,675 कार्यात्मक सीएससी, जिनमें से 3,00,955 ग्राम पंचायत (जीपी) स्तर पर कार्यरत हैं।

(ग): महाराष्ट्र में, कुल 43,198 सीएससी कार्यरत हैं, जिनमें से 32,179 ग्राम पंचायत (जीपी)/ग्राम स्तर पर कार्यरत हैं।

(घ) : किसी भी व्यक्ति/नागरिक के पास इलाके में नागरिक को सेवाएं देने के लिए आवश्यक आईसीटी बुनियादी ढांचे के साथ एक केंद्र स्थापित करने की क्षमता है, वह ग्राम स्तरीय उद्यमी (वीएलई) के रूप में पंजीकरण के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकता है और वीएलई बन सकता है।

(ड.) : डिजिटल इंडिया ने नाटकीय रूप से सरकार और ग्रामीण नागरिकों के बीच की दूरी को काफी कम कर दिया है। इसके अलावा, डिजिटल इंडिया ने बिना किसी रिसाव के और सीधे ग्रामीण भारत में पर्याप्त सेवाओं के वितरण में मदद की है। डिजिटलीकरण और प्रौद्योगिकी ने ग्रामीण भारत में प्रमुख कार्यात्मक डोमेन की सुविधा प्रदान की है, जिसमें ई-गवर्नेंस सेवाएं, बैंकिंग और वित्तीय सेवाएं, शैक्षिक और स्वास्थ्य सेवाएं, मोबाइल / डीटीएच रिचार्ज, ई-टिकटिंग सेवाएं, ऑनलाइन शॉपिंग आदि शामिल हैं, जो ग्राम स्तर के उद्यमियों (वीएलई) द्वारा गांव और ग्राम पंचायत (जीपी) स्तर पर इसके सामान्य सेवा केंद्रों के माध्यम से चलाए जाते हैं।।

****

अनुबंध-I

(क) : इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (एमईआईटीवाई), भारत सरकार ने डिजिटल एक्सेस, डिजिटल समावेशन ,डिजिटल सशक्तिकरण और डिजिटल डिवाइड को पाटना सुनिश्चित करके भारत को डिजिटल रूप से सशक्त समाज और ज्ञान-आधारित अर्थव्यवस्था में बदलने की दृष्टि से 'डिजिटल इंडिया' कार्यक्रम शुरू किया है। । डिजिटल इंडिया कार्यक्रम तीन प्रमुख विजन क्षेत्रों पर केंद्रित है, अर्थात् प्रत्येक नागरिक के लिए एक प्रमुख उपयोगिता के रूप में डिजिटल इन्फ्रास्ट्रक्चर, मांग पर शासन और सेवाएं और नागरिकों का डिजिटल सशक्तिकरण। डिजिटल इंडिया एक व्यापक कार्यक्रम है जिसमें विभिन्न केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों और राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों की कई परियोजनाएं शामिल हैं। देश भर में डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के तहत एमईआईटीवाई द्वारा की गई कुछ प्रमुख पहलें इस प्रकार हैं:

• **आधार:** आधार 12 अंकों की बायोमेट्रिक और जनसांख्यिकी आधारित पहचान प्रदान करता है जो अद्वितीय, आजीवन, ऑनलाइन और प्रामाणिक है। इसके अलावा, आधार को वैधानिक समर्थन देने के लिए, 'आधार (वित्तीय और अन्य सब्सिडी, लाभ और सेवाओं का लक्षित वितरण) अधिनियम, 2016' को 26 मार्च 2016 को अधिसूचित किया गया था। 129.90+ करोड़ से अधिक निवासियों को नामांकित किया गया है।

• **सामान्य सेवा केंद्र (सीएससी):** सामान्य सेवा केंद्र सेवा (नागरिक के लिए सरकार और नागरिकों के लिए व्यापार) वितरण केंद्र हैं। ग्राम पंचायत स्तर पर 3.00 लाख सीएससी सहित अब तक 3.99 लाख सामान्य सेवा केंद्र कार्यरत हैं।

• **डिजिटल विलेज:** एमईआईटीवाई ने अक्टूबर, 2018 में 'डिजिटल विलेज पायलट प्रोजेक्ट' भी शुरू किया है। इस परियोजना के तहत 700 ग्राम पंचायतों (जीपी)/गांवों में कम से कम एक ग्राम पंचायत/प्रति जिला प्रति राज्य/केंद्र शासित प्रदेश शामिल हैं। पेशकश की जा रही डिजिटल सेवाओं डिजिटल स्वास्थ्य सेवाएं, शिक्षा सेवा, वित्तीय सेवाएं, कौशल विकास, सौर पैनल संचालित स्ट्रीट लाइट सहित विभिन्न सरकार से नागरिक सेवाएं (जी 2 सी), व्यवसाय से नागरिक (बी 2 सी) सेवाएं हैं।

• **डिजिटल लॉकर:** डिजिटल लॉकर जारीकर्ताओं के लिए डिजिटल रिपॉजिटरी में दस्तावेजों को अपलोड करने के लिए रिपॉजिटरी और गेटवे के संग्रह के साथ एक पारिस्थितिकी तंत्र प्रदान करता है। वर्तमान में, डिजी लॉकर के 6.7 करोड़ से अधिक पंजीकृत उपयोगकर्ता हैं और 432 करोड़ प्रामाणिक दस्तावेज जारी किए गए हैं। 1227 जारीकर्ता और 171 अनुरोधकर्ता संगठनों को शामिल किया गया है।

• **ई-डिस्ट्रिक्ट एमएमपी का राष्ट्रीय रोलआउट:** ई-डिस्ट्रिक्ट एक मिशन मोड प्रोजेक्ट (एमएमपी) है जिसका उद्देश्य जिला या उप-जिला स्तर पर पहचान की गई उच्च मात्रा में नागरिक केंद्रित सेवाओं की इलेक्ट्रॉनिक डिलीवरी करना है। 28 राज्यों/ 6 केंद्र शासित प्रदेशों के 709 जिलों में कुल 3,916 ई-जिला सेवाएं शुरू की गई हैं।

• **ओपन सरकार डेटा प्लेटफ़ॉर्म:** ओपन गवर्नमेंट डेटा (ओजीडी) प्लेटफ़ॉर्म भारत सरकार की ओपन डेटा पहल का समर्थन करने के लिए एक प्लेटफ़ॉर्म है। यह सरकार के कामकाज में पारदर्शिता बढ़ाने का इरादा रखता है और विभिन्न दृष्टिकोणों को देने के लिए सरकारी डेटा के कई और नवीन उपयोगों के लिए रास्ते भी खोलता है। वर्तमान में, 179 मंत्रालयों/विभागों और राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा 10,624 कैटलॉग के तहत 508,548 संसाधन प्रकाशित किए गए हैं।

• **ई-अस्पताल/ऑनलाइन पंजीकरण प्रणाली (ओआरएस):** ई-अस्पताल के तहत ऑनलाइन पंजीकरण प्रणाली (ओआरएस) में नए रोगियों द्वारा ऑनलाइन नियुक्ति और पंजीकरण, प्रयोगशाला रिपोर्ट देखना, रक्त की उपलब्धता की स्थिति की जांच करना और भुगतान गेटवे (पेगव) के साथ एकीकरण शामिल है। अब तक ओआरएस के माध्यम से 367+ अस्पतालों में 40.55 लाख ऑनलाइन अप्वाइंटमेंट किए जा चुके हैं।

• **एनसीओजी-जीआईएस अनुप्रयोग:** राष्ट्रीय भू-सूचना विज्ञान केंद्र (एनसीओजी) परियोजना, विभागों के लिए साझाकरण, सहयोग, स्थान आधारित विश्लेषण और निर्णय समर्थन प्रणाली के लिए विकसित एक जीआईएस मंच है। अब तक विभिन्न क्षेत्रों में 598 आवेदन कार्य कर रहे हैं।

• **नए युग के शासन के लिए एकीकृत मोबाइल एप्लिकेशन (उमंग):** प्रमुख सरकारी सेवाओं को वितरित करने के लिए उमंग को एकल मोबाइल प्लेटफॉर्म के रूप में विकसित किया गया है। उमंग प्लेटफॉर्म पर 257 विभागों (केंद्र और राज्यों) की लगभग 21,531 सेवाएं पहले से ही उपलब्ध हैं।

• **माइगव** : माइगव भारत में सहभागी शासन के लिए अपनी तरह का पहला नागरिक जुड़ाव मंच है। माइगव का उद्देश्य नागरिकों और सरकार के बीच संवाद को सुविधाजनक बनाना, नागरिकों को सरकार के करीब लाना और सरकार को इस मंच के माध्यम से नागरिकों के करीब लाना है। वर्तमान में, 1.85 करोड़ से अधिक उपयोगकर्ता माइगव के साथ पंजीकृत हैं, माइगव प्लेटफॉर्म पर आयोजित विभिन्न गतिविधियों में भाग ले रहे हैं।

• **राष्ट्रीय ज्ञान नेटवर्क:** एनकेएन का उद्देश्य देश भर के सभी ज्ञान संस्थानों को उच्च गति डेटा संचार नेटवर्क के माध्यम से जोड़ना है ताकि संसाधनों और सहयोगी अनुसंधान को साझा करने के लिए प्रोत्साहित किया जा सके। उच्च शिक्षा और अनुसंधान के संस्थानों को आपस में जोड़ने के लिए एक उच्च गति डेटा संचार नेटवर्क स्थापित किया गया है। अब तक संस्थानों के 1746 लिंक चालू किए जा चुके हैं और उन्हें चालू कर दिया गया है। 517 एनकेएन लिंक पूरे भारत में एनआईसी जिला केंद्रों से जुड़े हैं।

• **जीवन प्रमाण:** जीवन प्रमाण के रूप में जानी जाने वाली पेंशनभोगियों के लिए डिजिटल जीवन प्रमाणपत्र योजना में जीवन प्रमाण पत्र हासिल करने की पूरी प्रक्रिया को डिजिटल बनाने की परिकल्पना की गई है। इस पहल के साथ, पेंशनभोगी को संवितरण एजेंसी या प्रमाणन प्राधिकरण के सामने खुद को शारीरिक रूप से प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं है। 2014 से अब तक 4.57 करोड़ से अधिक डिजिटल जीवन प्रमाणपत्र संसाधित किए जा चुके हैं।

• **प्रधान मंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान (पीएमजीदिशा):** सरकार ने 6 करोड़ ग्रामीण परिवारों (प्रति परिवार एक व्यक्ति) को कवर करके ग्रामीण भारत में डिजिटल साक्षरता की शुरुआत करने के लिए "प्रधान मंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान (पीएमजीदिशा)" नामक एक नई योजना को मंजूरी दी है। अब तक 4.16+ करोड़ उम्मीदवारों को प्रशिक्षण दिया गया है और इसमें से 3.07+ करोड़ से अधिक उम्मीदवारों को प्रमाणित किया गया है। यह योजना देश के सभी ग्रामीण क्षेत्रों में लागू है।

• इलेक्ट्रॉनिकी विनिर्माण

○ संशोधित विशेष प्रोत्साहन पैकेज (एम-सिप्स): जून 2021 तक, लगभग 81,895 करोड़ रु. के प्रस्तावित निवेश के साथ 306 आवेदन स्वीकृत किए गए हैं।
○ इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण क्लस्टर (ईएमसी): ईएमसी योजना के तहत, 1577 करोड़ रुपये की सरकारी सहायता अनुदान सहित 3,898 करोड़ रुपये परियोजना लागत के साथ 3,565 एकड़ क्षेत्र में 20 ग्रीनफील्ड ईएमसी और 3 सामान्य सुविधा केंद्र (सीएफसी) देश भर के 15 राज्यों में मंजूर किए गए हैं। देश में इलेक्ट्रॉनिकी उद्योग के लिए बुनियादी ढांचे के आधार को और मजबूत करने और इलेक्ट्रॉनिकी मूल्य श्रृंखला को गहरा करने के लिए संशोधित इलेक्ट्रॉनिकी विनिर्माण क्लस्टर (ईएमसी 2.0) योजना 1 अप्रैल, 2020 को अधिसूचित की गई है।

****